

2.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी सं. 4 से 10 व 12 से एवं 16 के वकील उपस्थित। शेष की तलबी व मौका रिपोर्ट इंतजार।

विप्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली का पूर्वालोकन करते हुए उभय पक्ष को सुना गया।

विप्रार्थीगण के वकील की बहस है कि भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:पं.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प. 3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित सलंगन नजरी नक्शे अनुसार राजस्व ग्राम भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा, तहसील सिणधरी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8,9/1,19,20/1, 21, 22, 24,24/1 व 24/2 में से होकर गुजरने वाले कृदिमी मार्ग को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण में सलंगन नजरी नक्शा के अनुसार भाटा-मीठा सड़क से भाटा मोड़सिंह विद्यालय तक पहुंचने की मंशा को लेकर प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कि वर्तमान में उक्त रास्ता बीच में विशनोईयों की ढाणी तक ही रोक दिया गया है तथा खसरा नम्बर 19 जो कि सेढ़ा पडौसियों के विवाद की दशा में सीमांकन कार्यवाही हेतु विचाराधीन है को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन को निरस्त फरमाया जावे कि बाद सीमांकन के मौके पर विवाद रहित स्थिति होने की दशा में हम समस्त खातेदारन द्वारा अपनी-अपनी जोत का आमजन के हितार्थ विधिवत रूप से रास्ते के रूप में भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करते हुए दी जायेगी।

इसके विपरित पैरोकार सरकार की बहस है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि मौके पर कदीमी रास्ता है अथवा नहीं। लिहाजा मौका रिपोर्ट की तलबी पश्चात् गुणावगुण के निर्णय पारित किया जावे।

हमने प्रार्थी के पैरोकार की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पूर्व में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा वक्त क्षेत्र में भ्रमण मौका स्थिति के तथ्यों के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया जिसे मददेनजर रखते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों तथा परिशिष्ट एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के परस्पर अद्यतन करते हुए मिलान करने पर पाया गया कि मौके पर कदीमी रास्ता पूर्व में अवस्थित था जो कि अधिकांश प्रकरण में अवस्थित पक्षकारान के आवागमन हेतु प्रयुक्त होता था, परन्तु वर्तमान में उक्त रास्ते के आवागमन को विशनोईयों की ढाणी तक ही खुला रखा गया है, उससे आगे बाधित कर रखा है। उक्त रास्ते को बाधित रखे जाने का मुख्य कारण खसरा नम्बर 19 के

सिणधरी
अधिकारी

पक्षकारान की ओर से सीमांकन की विचाराधीन कार्यवाही पूर्ण नहीं होना है। इस सन्दर्भ में वक्त भ्रमण पीठासीन अधिकारी के ध्यान में भी लाया गया कि सीमांकन के विवाद की दशा में उक्त रास्ता बाधित है, यदि बाद सीमांकन के मेगवाल एवं कलबी समुदाय के बीच वाद विवाद के निपटारे उपरांत आपसी सहमति/ समझाईश से हस्तगत रास्ता प्रकरण पर विधिवत प्रक्रिया अमल में लाई जाकर समस्त सहखातेदार अपनी अपनी रजानुसार सुविधा के अनुरूप रास्ता देने की मंशा को ध्यान में रखते हुए यदि पक्षकारान की विधिवत रायसुमारी से रास्ता छोड़ा अथवा राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे, तो अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तथा ग्रामीण परिवेश में लोगों के आपसी सदभाव एवं भाईचारे की कौमी एकता की मिसाल भी कायम रह सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अदालत यह उचित समझती है कि जब तक खसरा नम्बर 19 के खातेदार व उनके सेढा पड़ोसी खातेदारों के बीच सीमांकन संबंधी दुरुस्ती का निपटारा नहीं हो तक विवादित रास्ता प्रकरण को ओर अधिक विवाद अथवा दुविधा के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाकर स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को प्रतिपादित नहीं करने तथा मौका स्थिति अनुसार विवादग्रस्त होने तथा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसी स्तर पर खारिज किया गया है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो एवं नम्बर से कम हो।


मजिस्ट्रेट अधिकारी
सिणधरी